

टीएमसी के विधायकों ने जो किया वही सांसद भी करने जा रहे हैं

अटकलें हैं कि लगभग 20 सांसद टीएमसी छोड़ने की तैयारी में हैं, उन्हें भी अभिषेक बनर्जी के नियंत्रण से परेशानी महसूस हो रही है

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 जून। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के बाद अब बारी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की है।

एसी जोरदार अफवाहें चल रही हैं कि सांसद भी उसी राह पर बढ़ रहे हैं, जिस पर पहले विधायक चले थे। कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के अधिकांश सांसद अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को छोड़कर बागी विधायकों के साथ जाने पर विचार कर रहे हैं।

हालांकि सांसदों के पलायन के स्पष्ट संकेत अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन खबरें हैं कि उनमें से कुछ अलग समूह बनाने और विधानसभा में अपने बागी साथियों के साथ जुड़ने की योजना बना रहे हैं। इस विद्रोह का निशाना इस बार भी ममता बनर्जी से अधिक, उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी हैं।

एसे विद्रोह और राजनीतिक संकट

■ पार्टी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि जल्दी ही अधिकांश सांसद पार्टी छोड़कर ऋतब्रत के खेमे में आ जाएंगे।

■ टीएमसी में ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अभिषेक बनर्जी के मातहत काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन, ममता बनर्जी का अपने भतीजे पर अगाध स्नेह है। यह भी खबरें हैं कि चुनावी हार के बाद हुई मीटिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी खड़े होकर अभिषेक बनर्जी के लिए ताली बजाने को मजबूर किया गया।

■ पार्टी नेताओं द्वारा एक के बाद एक मिल रहे झटके के बीच तृणमूल सुप्रिमो ममता बनर्जी को अपने पूर्व सहयोगी के हाथों सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा। ममता भवानीपुर से चुनाव हार चुकी हैं और वे विधानसभा सदस्य नहीं हैं। ममता के पूर्व विश्वस्त हुमायूं कबीर ने चुनाव से पहले ही टीएमसी छोड़ दी थी, वे दो सीटों से विजयी हुए हैं। उन्होंने एक सीट ममता को देने की पेशकश की और कहा, ममता बनर्जी खुद उनके पास आकर सीट देने की याचना करें।

के बीच ममता बनर्जी को उनके ही एक पूर्व करीबी सहयोगी से सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर चुनाव से पहले ही ममता का साथ छोड़ चुके थे। उन्होंने दो सीटों से चुनाव जीता था और अब उन्हें एक

सीट खाली करनी है।

अब वे उन दोनों सीटों में से एक सीट ममता बनर्जी को देने की पेशकश कर रहे हैं, ताकि उन्हें विधानसभा में वापसी का एक जरिया मिल सके। ममता अपने गृह क्षेत्र भवानीपुर से वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथों चुनाव हार गई थीं। लेकिन हुमायूं की एक शर्त है-

ममता बनर्जी को स्वयं उनके पास जाकर उस सीट के लिए अनुरोध करना होगा। हुमायूं को भी पार्टी पर अभिषेक बनर्जी के बढ़ते नियंत्रण से नाराजगी थी।

अब पार्टी का कोई भी सदस्य अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में काम करने को राजी नहीं है और अब वे लोग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पूर्व मंत्री महेश जोशी व संजय बडाय आदि के खिलाफ जांच लंबित रखी।

अदालत ने फिलहाल आरोप पत्र को रिपोर्ट कैटेगरी में रखा है।

एसीबी की ओर से आरोप पत्र के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेज पेश कर अपराध की कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों सहित संपूर्ण आरोप पत्र करीब 17 हजार पृष्ठों पर फैला हुआ है। पूर्व में विभाग के रिटायर व वर्तमान अधिकारियों दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गोडु, महेंद्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक और निरिल कुमार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। इसके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीजेपी को रैली की अनुमति नहीं देगी केन्द्र सरकार

सीजेपी फाउण्डर 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे और सीधे ही पुलिस थाने जाकर जंतर-मंतर पर रैली की अनुमति मांगेंगे

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जून। सूत्रों के अनुसार, कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके को 6 जून को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद सीधे गिरफ्तार किए जाने की संभावना कम है, लेकिन उन्हें उसी दिन जंतर-मंतर पर एक रैली आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति नहीं मिलेगी। यह रैली नीट परीक्षा पेपर लोकविवाद के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए की जानी है।

आमतौर पर जंतर-मंतर पर किसी प्रदर्शन के लिए कम से कम एक सप्ताह पहले अनुमति लेनी होती है, लेकिन दिपके ने कहा है कि दिल्ली पहुंचते ही वे सीधे संसद मार्ग थाने जाएंगे और उसी दिन रैली की अनुमति मांगेंगे। यह दावा एक ओर भोला-भाला और वास्तविकता से दूर लगता है, तो दूसरी तरफ संदेह पैदा करता है। इसको लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इनमें से एक यह है कि सीजेपी को आरएसएस का समर्थन और वित्तीय सहायता प्राप्त है, ठीक वैसे ही, जैसे अपने शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी के बारे में आरोप लगाए गए थे।

■ यह भी अटकलें हैं कि उन्हें दिल्ली आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस संभावना से इन्कार किया है।

■ सीजेपी ने यह रैली नीट परीक्षा प्रणाली की विफलता के खिलाफ आयोजित की है, उनकी मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा है।

■ नियमानुसार जंतर-मंतर पर रैली के लिए एक सप्ताह पहले अनुमति लेनी पड़ती है, पर, दिपके 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे और उसी दिन रैली के आयोजन की अनुमति मांगेंगे और पूरी संभावना है कि उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी।

■ सीजेपी को लेकर कई अटकलें चल रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कि जैसे आप को आरएसएस का समर्थन था, वैसे ही सीजेपी को भी संघ से समर्थन व सहायता मिल रही है।

दिखावटी संगठन बताया है और कहा है कि उसके पास कोई गहरी नीतिगत सोच नहीं है। कुछ विपक्षी दल चाहते हैं कि सीजेपी खुद को अधिक स्पष्ट रूप से भाजपा-विरोधी रुख के साथ जोड़े, बजाय इसके कि वह केवल "सत्ता विरोधी रुख" का एक आम दावा करे। मई के मध्य में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े एक युवा द्वारा शुरू किया गया,

सीजेपी एक व्यंग्यात्मक युवा आंदोलन है, जो बेरोजगारी, परीक्षा पेपर लीक (विशेषकर नीट 2026), शिक्षा व्यवस्था की खामियों और शासन की विफलताओं जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। अस्तित्व में आए मात्र 15 दिनों के भीतर ही सीजेपी ने सोशल मीडिया पर भारी लोकप्रियता हासिल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केरल में मानसून ने दी दस्तक, दिल्ली हुई तरबतर

दिल्ली एनसीआर में मौसम ने नाटकीय करवट ली और भारी वर्षा हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 जून। गुरुवार को मौसम ने नाटकीय करवट ली और दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर) में दोपहर का समय सांझ जैसा दिखाई देने लगा। घने बादलों और जबरदस्त धूलभरी आंधियों ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया।

जिस दिन (गुरुवार) दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में प्रवेश किया, उसी दिन दिल्ली और एनसीआर में भी मौसम ने अप्रत्याशित रूप से करवट बदली। काले बादल, तेज धूलभरी आंधियां और भारी वर्षा ने अपराह्न काल में ही अंधेरे जैसा माहौल पैदा कर दिया।

दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच, नोएडा और आसपास के इलाकों में आसमान इतना काला हो गया कि लोगों

■ इतने घने बादल छाए कि भारी दोपहरी में अंधकार सा लगने लगा, लोगों को गाड़ियों की हैंडलाइट्स जलानी पड़ीं। बारिश से शहर के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट आ गई।

■ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 5 जून तक के लिए क्षेत्र में यलो अलर्ट जारी किया है और दिल्ली एनसीआर में आंधी-तूफान की संभावना जताई है।

■ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अधिकृत घोषणा की कि केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून पहुंच गया है और इसके साथ वर्षा ऋतु के आगमन की घोषणा कर दी गई।

को रात जैसा महसूस होने लगा। वाहन चालकों को कम दृश्यता के कारण हेडलाइट्स जलानी पड़ीं। हालांकि इस तूफान ने भीषण गर्मी से राहत दी, लेकिन तेज हवाओं और उड़ती धूल ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। अचानक हुए इस मौसमी बदलाव

के कारण जबरदस्त धूलभरी आंधियां चलीं, जिनके कारण सड़कों पर पड़ा मलबा, पत्ते और धूल उड़ने लगी। इससे प्रमुख मार्गों पर पैदल और वाहन यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। अंधकार और तेज हवाओं के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंग

भोपाल, 04 जून (हि.सं.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन को बेटी दीक्षा कुशवाहा ने मात्र 22 मिनट में आठ मिलीमीटर आकार के चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड

■ मध्यप्रदेश उज्जैन की दीक्षा कुशवाहा ने 22 मिनट में चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाई और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया।

वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर दीक्षा को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी।

उज्जैन के ऋषि नगर निवासी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ईरान वॉर से अमेरिकन सैनिक वापस बुलाए जाएं’

अमेरिका में हाउस ऑफ रैप्रिजेंटेटिव्स ने प्रस्ताव पारित कर ट्रंप को निर्देश दिया

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जून। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ईरान युद्ध से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया गया है। यह कदम मुख्य रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है, लेकिन इससे राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को एक राजनीतिक झटका जरूर लगा है।

ट्रंप की बहुमत वाली रिपब्लिकन पार्टी के चार सदस्यों ने इस कदम का समर्थन करने में डेमोक्रेट्स का साथ दिया। यह प्रस्ताव 215-208 वोटों से पारित होकर सीनेट में गया है, लेकिन अंततः इसे राष्ट्रपति के वीटो का सामना करना पड़ेगा।

हाउस फ्रैंच अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, "यह अमेरिकी

■ हालांकि, हाउस ऑफ रैप्रिजेंटेटिव्स का यह प्रस्ताव एक प्रतीकात्मक कदम है। पर, यह राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक करारा झटका है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के चार सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसकी वजह से 215 के मुकाबले 218 मतों से प्रस्ताव पारित हो गया। ऐसा पहली बार हुआ, जब रिपब्लिकन्स के नियंत्रण वाले हाउस ऑफ रैप्रिजेंटेटिव्स में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है।

■ डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला कर संविधान का उल्लंघन किया है। वॉर पावर्स एक्ट के तहत किसी युद्ध में अमेरिकी सेना तैनात करने के बाद 60 दिनों में कांग्रेस की अनुमति लेनी चाहिए। पर वह अवधि कई सप्ताह पहले ही गुजर चुकी है।

जनता की ओर से डॉनल्ड ट्रंप को दिया गया जोरदार और स्पष्ट संदेश है कि अब समय आ गया है कि ईरान में उनके बेहद

अलोकप्रिय और अवैध युद्ध को समाप्त किया जाए।" ऐसा पहली बार हुआ है, जब

रिपब्लिकन बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा ने युद्ध शुरू होने के तीन महीने बाद ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया है, जिसका उद्देश्य ट्रंप को तैरान के खिलाफ सैन्य युद्ध सीमित करने के लिए मजबूर करना है।

डेमोक्रेट्स का मानना है कि यह मतदान युद्ध और शांति से जुड़े फैसलों में कांग्रेस की संवैधानिक भूमिका को फिर से स्थापित करने के उनके प्रयासों में एक संभावित निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

ऐसा ही एक प्रस्ताव मई के अंत में सीनेट में एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक चरण पार कर चुका है। रिपब्लिकन बहुमत वाली सिनेट में भी इसे इसी सप्ताह पारित किया जा सकता है। हालांकि रिपब्लिकन नेतृत्व अंतिम मंजूरी को रोकने की कोशिश कर सकता है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली अग्निकांड पर होटल मालिक चार दिन की पुलिस हिरासत में

नई दिल्ली, 04 जून। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार किए गए होटल मालिक लवकेश बजाज को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार

■ दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर गुरुवार को अदालत में पेश किया।

करने के बाद गुरुवार को कोर्ट में पेश किया।

पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने चार दिनों की हिरासत की मांग की। सुनवाई के दौरान लवकेश बजाज के वकील ने कहा कि उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। इस पर दिल्ली (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओटीएस चौराहे पर फ्लाइओवर बनाने के लिए नई डी.पी.आर. बनाने का आदेश रद्द

हाईकोर्ट ने पूर्व में जेसीएल इंफ्रा कंपनी को साँपे गए प्रोजेक्ट की निविदा रद्द करने के आदेश को भी निरस्त किया

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर । जेएलएन मार्ग स्थित ओटीएस चौराहे, जो ट्रेफिक जाम के लिए सबसे कुख्यात चौराहा है, को जाम फ्री और सिग्नल फ्री करने तथा एक फ्लाइओवर, सब-वे निर्माण व सौंदर्यीकरण कार्य के 184.30 करोड़ रुपये के 2022 के टेंडर को रद्द करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेडीए) को फटकार लगाया है।

ज्ञात रहे कि यह निविदा पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2022 में जारी हुई थी। कंपनी को 5 जनवरी 2024 तक यह यह प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन जेडीए प्रशासन ने एमएनआईटी

और ओटीएस से जमीन ही अवाप्त नहीं की। इसके विपरीत, जेडीए ने इस निविदा को 24 अप्रैल 2024 को रद्द करते हुए ओटीएस चौराहे पर फ्लाइओवर के लिए 83 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाइओवर की नई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने की निविदा जारी कर दी। जेडीए द्वारा पूर्व के टेंडर निरस्त करने को चुनौती देते हुए जेसीएल इंफ्रा प्रा. लि. ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने 83 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर बनाने के टेंडर

■ अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि, जेडीए और जेसीएल इंफ्रा के बीच हुए अनुबंध को निरस्त करने के कारणों की जांच करवाएं, साथ ही दोषी अफसरों पर 2 माह में कार्रवाई करें।

■ अदालत ने जेडीए को फटकारते हुए कहा कि "इस प्रकरण में जेडीए के प्रभारी अधिकारी की ओर से कोर्ट में गलत बयानबाजी की गई है, जिसके तथ्य रिकॉर्ड से अलग पाए गए हैं, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।"

■ अधिवक्ता एस.एस. होरा ने कहा कि, याचिकाकर्ता कंपनी को दिया हुआ ठेका अकारण और सुनवाई किए बिना जेडीए ने वापस लिया है, जबकि कंपनी ने इंजीनियरिंग और डिजाइन तैयार कर अनुमोदन के लिए पेश कर दिए थे। यहां तक कि प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटा लिए थे, लेकिन जरूरी अनुमतियां व साइट पर जमीन मुहैया नहीं करवाने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका।"

आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने

जेडीए को कहा है कि वह पूर्व में हुए

अनुबंध के आधार पर ही प्रोजेक्ट को

आगे बढ़ाए। साथ ही, हाईकोर्ट ने पूर्व का अनुबंध निरस्त करने के कारणों की जांच करने के आदेश दिए हैं, ताकि जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय की जा सके। अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे दोषी अफसरों पर 2 माह में उचित कार्रवाई करें। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश जेसीएल इंफ्रा प्रा. लि. की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता कंपनी जेसीएल इंफ्रा की ओर से अधिवक्ता एस.एस.होरा तथा जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुंडी व अभियांत्रिकी निदेशक देवेन्द्र गुप्ता पैरवी के लिए पेश हुए थे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने 7 प्रत्याशी घोषित किए

नई दिल्ली, 04 जून। कांग्रेस ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद सात उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर

■ राजस्थान से नीरज डांगी और कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा के नाम घोषित

लगाई गई है। सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से जारी सूची के अनुसार, कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मध्य (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

बुद्धि से विचार कर किए गए कर्म ही सफल होते हैं। -महाभारत

तरसेंगे हम पीने के पानी को

पानी.... जीवन की वह मूलभूत आवश्यकता है जिससे मानव, पशु, और सारा जीव-जंतु जुड़ा हुआ है। परंतु आज जब हम शुद्ध पानी की बात करते हैं, तो यह केवल एक भौतिक आवश्यकता नहीं रह जाती; यह हमारे सभ्य जीवन का दर्पण बन जाती है। जिस देश में नदियाँ बहती हैं और वर्षा होती है, वहाँ भी अनेक स्थानों पर लोग उस एक गिलास साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। यह त्रासद स्थिति सिर्फ संसाधन की कमी नहीं, बल्कि नीतियों, प्रवर्तन, नेतृत्व, और समाज की प्राथमिकताओं की विफलता का संकेत है।

भारत विविधता की भूमि है। हिमालय की हिम-जलधाराएँ, समुद्रतटों की वर्षा-पवन प्रणालियाँ, पश्चिमी और पूर्वी नदी घाटियाँ सब मिलकर जल की एक समृद्ध तस्वीर पेश करते हैं। फिर भी स्नान के लिए पानी है, खेती के लिए पानी है, उद्योगों को पानी मिल जाता है, किंतु पीने के शुद्ध जल की उपलब्धता असमान और अक्सर अपर्याप्त है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र पीने के पानी की चुनौती से जूझ रहे हैं, पर कारण और प्रभाव भिन्न हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पाइपलाइन नेटवर्क, रिचार्ज की कमी, और प्रदूषण बड़े कारण हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी, भूजल का प्रदूषण, तथा जल-व्यवस्थापन की अपर्याप्त समझ मुख्य बाधाएँ हैं।

भूजल पर अत्यधिक निर्भरता ने समस्या को और जटिल बना दिया है। खेती में अनियंत्रित बोरेलव ड्रिलिंग, उद्योगों का अतिव्यापी उपयोग, और शहरी उपभोक्ता मांग ने पानी के स्तर को लगातार कम कर दिया है। परिणामस्वरूप नल सूखते हैं, हैडपम्प गड़बड़ा जाते हैं, और जो मिल भी जाता है वो अक्सर प्रदूषित। प्रदूषण का स्रोत भी बहुस्तरीय है: औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन (कीटनाशक और उर्वरक), घरेलू सीवेज, तथा ठोस अपशिष्ट जो जल स्रोतों में जा कर जल को जहरीला बना देते हैं। नदी और झीलें न केवल गंदी होती जा रही हैं, बल्कि हमारे औचित्यहीन उपयोग से कमजोर भी होती जा रही हैं।

जल संकट केवल भौतिक अभाव नहीं है; यह असमानता भी है। शहरों के धनी मोहल्लों में पानी की उपलब्धता बेहतर होती है जबकि श्रृंगी-झोपड़ी और ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र अभी भी रोज पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। यह असमानता स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। पानी से जुड़ी बीमारियाँ डायरिया, स्कर्वी नहीं, बल्कि जलीय रोगों की पुनरावृत्ति बच्चों की मृत्युदर और काम करने की क्षमता को कम करती हैं। महिलाएँ और बालिकाएँ पानी लाने की जिम्मेदारी में समय खो देती हैं, जिससे उनके शिक्षा और सामाजिक भागीदारी प्रभावित होती हैं।

समस्या की जड़ में जननीति और कार्यान्वयन की कमी भी है। कई योजनाएँ और नियम तो बने हैं, पर उनका क्रियान्वयन कमजोर है। जलमंडल पर आधारित योजना, लोकभागीदारी, और संस्थागत सहकारिता की आवश्यकता है। स्थानीय समाजों को सशक्त करके, पानी का सुरक्षित प्रबंधन और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। केवल नीतियाँ बनाना पर्याप्त नहीं; निगरानी, पारदर्शिता, और जवाबदेही उतनी ही जरूरी हैं ताकि योजना जमीन पर दिखे और असर दे।

हमारे पास समाधान भी हैं, और वे तकनीकी से लेकर पारंपरिक तक विस्तारित हैं। सबसे पहले जल संरक्षण और पुनः उपयोग को प्राथमिकता देनी होगी। वर्षा जल संचयन सरल और प्रभावी उपाय है, जिसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। छतों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर जल संचयन संरचनाएँ बनाकर वर्षा के पानी को रोक कर भूमिगत जलस्रोतों को रिचार्ज किया जा सकता है। साथ ही छोटे बाँध, तालाब, और अपशिष्ट जल के उपचार के बाद पुनः उपयोग, विशेषकर बागवानी और उद्योगों के लिए, पानी की मांग को कम कर देते हैं।

हमारे पास समाधान भी हैं, और वे तकनीकी से लेकर पारंपरिक तक विस्तारित हैं। सबसे पहले जल संरक्षण और पुनः उपयोग को प्राथमिकता देनी होगी। वर्षा जल संचयन सरल और प्रभावी उपाय है, जिसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। छतों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर जल संचयन संरचनाएँ बनाकर वर्षा के पानी को रोक कर भूमिगत जलस्रोतों को रिचार्ज किया जा सकता है। साथ ही छोटे बाँध, तालाब, और अपशिष्ट जल के उपचार के बाद पुनः उपयोग, विशेषकर बागवानी और उद्योगों के लिए, पानी की मांग को कम कर देते हैं।

हमारे पास समाधान भी हैं, और वे तकनीकी से लेकर पारंपरिक तक विस्तारित हैं। सबसे पहले जल संरक्षण और पुनः उपयोग को प्राथमिकता देनी होगी। वर्षा जल संचयन सरल और प्रभावी उपाय है, जिसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। छतों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर जल संचयन संरचनाएँ बनाकर वर्षा के पानी को रोक कर भूमिगत जलस्रोतों को रिचार्ज किया जा सकता है। साथ ही छोटे बाँध, तालाब, और अपशिष्ट जल के उपचार के बाद पुनः उपयोग, विशेषकर बागवानी और उद्योगों के लिए, पानी की मांग को कम कर देते हैं।

हमारे पास समाधान भी हैं, और वे तकनीकी से लेकर पारंपरिक तक विस्तारित हैं। सबसे पहले जल संरक्षण और पुनः उपयोग को प्राथमिकता देनी होगी। वर्षा जल संचयन सरल और प्रभावी उपाय है, जिसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। छतों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर जल संचयन संरचनाएँ बनाकर वर्षा के पानी को रोक कर भूमिगत जलस्रोतों को रिचार्ज किया जा सकता है। साथ ही छोटे बाँध, तालाब, और अपशिष्ट जल के उपचार के बाद पुनः उपयोग, विशेषकर बागवानी और उद्योगों के लिए, पानी की मांग को कम कर देते हैं।

कृषि में पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन, सूखी फसल चक्र और जल कुशल फसलें अपनाकर भी आवश्यकता है। किसान को प्रशिक्षित कर, सस्ता और उपलब्ध तकनीक प्रदान करके बड़े पैमाने पर जल उपयोग को घटाया जा सकता है। सिंचाई की योजना बनाते समय स्थानीय जल-स्तर और मौसमी पैटर्न का ध्यान रखना होगा, ताकि जमीन की उर्वरता और जल-स्तर दोनों सुरक्षित रहे।

नियमन और प्रदूषण नियंत्रण का कठोर पालन जरूरी है। उद्योगों और कस्बों से निकलने वाले सीवेज का उपचार अनिवार्य बनाना होगा। नदी घाटियों और जलाशयों के किनारों पर अतिक्रमण रोका जाए, और गंदगी ढेर करने वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाई जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के लिए जल गुणवत्ता मानक सख्त किए जाएँ और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता सार्व तंत्र को प्रभावी बनाना होगा।

जल प्रशासन में लोगों की भागीदारी अहम है। जल उपयोग, संरक्षण और वितरण से जुड़े निर्णयों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर सकता है। पंचायत स्तर पर जल समितियाँ काम कर सकती हैं जो पानी के उपयोग के नियम बनाएँ, रिचार्ज परियोजनाओं पर निगरानी रखें और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करें। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों से लोग सरल व्यवहारिक बदलाव जैसे नल बंद रखना, गंदा पानी न बहाना, और घरेलू उपचार अपनाना करने के लिए प्रेरित होंगे।

प्रौद्योगिकी भी इस संकट में सहायक हो सकती है। सस्ती जल परीक्षण किटें, स्मार्ट मीटरिंग, और डेटा-आधारित जल प्रबंधन से आपूर्ति और मांग का संतुलन बनाया जा सकता है। उपग्रह और जियो डेटा भूजल स्तर की निगरानी में मदद करते हैं और समय पर हस्तक्षेप संभव बनाते हैं। पर तकनीक तभी फलदायी होगी जब वह स्थानीय संदर्भ में लागू हो और समुदाय के हाथ में सेवा की तरह पहुँचे, न कि महँगी और जर्जर परियोजनाओं की तरह।

अर्थव्यवस्था भी एक कारक है। पानी को सस्ती और असीम संसाधन मानकर उपयोग करना महँगा पड़ रहा है। पानी की असल कीमत और उसकी बाह्य लागतों (जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, पुनर्स्थापन) को समझ कर नीति निर्माताओं को पानी के प्रबंधन के आर्थिक मांडल बनाए जाने चाहिए। टैक्स नीति, सब्सिडी का निर्धारण और पानी के उचित मूल्य निर्धारण से गैर-जरूरी उपयोग को रोका जा सकता है, किंतु इसके साथ सामाजिक सुरक्षा की भी व्यवस्था आवश्यक है ताकि गरीबों की आजीविका प्रभावित न हो।

हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल भी पानी की रक्षा के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। इतिहास में जल-पूजन, तालाब, और पवित्र नदियों की परंपरा रही है जो केवल जल का धार्मिक महत्व ही नहीं, सामाजिक साझा करने का बोध भी देती है। इस संवेदनशीलता को फिर से जगाकर और इसे आधुनिक सबक के साथ जोड़कर हम पानी के प्रति सम्मान और संरक्षण का भाव बढ़ा सकते हैं।

यदि हम आज भी देर करें तो आने वाली पीढ़ियाँ वही सवाल करेंगी जो हमने पूछा: हमने क्या किया? क्या हमने अपने नदियों, तालाबों और भूमिगत जल को बचाया? जवाब तभी सकारात्मक होगा जब नल, तकनीक, समुदाय और संस्कृति एक साथ काम करें। पानी के हर एक बूंद का महत्व समझें; नल से बहती पानी की हर बूंद की कीमत जानें; वर्षा को रोके नहीं, सन्भालें; और अपने बच्चों को पानी का सम्मान सिखाएँ। तभी हम उस दिन से बच पाएँगे जब सचमुच हर गली, हर घर में “तरसेंगे हम पीने के पानी को” केवल एक कड़वी याद न बन कर एक चेतावनी ही बनी रहे।

-अतिथि संपादक
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार



मणिमाला शर्मा

एक समय जल-संरक्षण की मिसाल रहा जयपुर आज अति-दोहित भू-जल, प्रदूषण और अतिक्रमण के बोझ तले कराह रहा है। सवाल यह है कि क्या शहर अपनी खोई हुई जल-स्मृति को वापस पा सकेगा।

हम एक ऐसे आत्मघाती और संवेदनहीन दौर में जी रहे हैं जहाँ प्यास से तड़पते गले और सूखती नदियाँ भी हमारी सोई हुई चेतना को जगाने में नाकाम साबित हो रही हैं। हर साल पांच जून को पर्यावरण दिवस के नाम पर रस्मी तौर पर कुछ सरकारी पौधे रोप देना, वालानुकूलित कपारों में बैठकर जल संकट पर चिंता जताना और प्रकृति-प्रेम का ढोंग चना हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन इस पाखंड की ओट में छिपा डकठान सच यह है कि जब हम मंचों से देते हैं कि खोखली दुहाई दे रहे होते हैं, तब तक राजधानी जयपुर की एक बड़ी आबादी पानी की एक-एक बूंद के लिए सड़कों पर टैकरो के पीछे भागने को अभिशप्त हो चुकी होती है। शहर अब पूरी तरह कंक्रीट के जंगल में बंदील होने के कगार पर पहुँच चुका है। पहले चारों ओर हरियाली

दिखाई देती थी वही अब बहुमंजिली इमारतों ने हरियाली की जगह ले ली है। हरियाली अब बस बालकनी और छतों पर तखे हुए गमलों में सिमट कर रह गई है। इसका मुख्य संकट जल संकट के रूप में सामने आया है। जयपुर का जल संकट अब कोई दूर की कौड़ी या भविष्य की चेतावनी नहीं है; यह हमारे वर्तमान का वह जलला हुआ यथार्थ है जो हमारी चौखट तक आकर हमें निगलने को तैयार खड़ा है। इस संकट का सबसे खतरनाक चेहरा देखा जा रहा है जो हमारी चौखट तक आकर हमें निगलने को तैयार खड़ा है। इस संकट का सबसे खतरनाक चेहरा देखा जा रहा है जो हमारी चौखट तक आकर हमें निगलने को तैयार खड़ा है।

इस रिपोर्ट के चौकाने वाले आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि जयपुर जिला पूरी तरह अति-दोहित यानी क्षमता से अधिक शोषित की श्रेणी में आ चुका है। इस रिपोर्ट के चौकाने वाले आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान के कुल तीन सौ दो भू-जल क्षेत्रों में से सत्तर प्रतिशत से अधिक यानी दो सौ चौदह क्षेत्र अति-दोहित यानी क्षमता से अधिक शोषित की श्रेणी में आ चुके हैं। जयपुर शहर के भीतर और बाहरी औद्योगिक क्षेत्रों में पानी का दोहन इसकी प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता से कई गुना ज्यादा है। हम पताल से लगातार पानी खींच रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में भू-जल का झूर खनन कहा जाता है।

इसमें भू-जल निकालने की रफतार राज्य के रीचार्ज होने की रफतार से 1.49 फीसदी अधिक है। यानी हम आने वाली पीढ़ियों के हिस्से का पानी आज ही निचोड़ रहे हैं। हम केवल अपना आज

विश्व पर्यावरण दिवस विशेष (5 जून).....

जयपुर: छह सौ बावड़ियों का विलाप

भू-जल के अंधाधुंध दोहन, कंक्रीट विस्तार और नीतिगत लापरवाही ने पारंपरिक जल संरचनाओं को किया खत्म

नहीं उजाड़ रहे, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के हिस्से का जीवन भी आज ही खींचकर खत्म कर रहे हैं। इस भयानक तबाही का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने आधुनिकता के नशे में चूर होकर जयपुर की सदियों पुरानी जल-प्रणालियों को बेरहमी से हत्या कर दी।

महाराजा सवाई जयसिंह और उनके बाद के दूरदर्शी शासकों ने जब इस शहर को बसाया था, तो इसके जल प्रबंधन के लिए एक अभूतपूर्व ढांचा तैयार किया था। इतिहासकारों के अनुसार, जयपुर के परकोटे और उसके आस-पास पानी सहेजने के लिए छह सौ से अधिक कुआँ और बेजोड़ बावड़ियों का एक ऐतिहासिक जाल बिछाया गया था। लेकिन तथाकथित स्मार्ट और आधुनिक बनने की होड़ में हमने क्या किया? हमने उन छह सौ ऐतिहासिक जल-स्रोतों को जमींदोज कर दिया। आज हालत यह है कि उन छह सौ जल स्रोतों में से आज गिनती की वीस बावड़ियाँ भी ठीक से सांस नहीं ले पा रही हैं। प्ला मीणा का कुंड, सागर बावड़ी या चोला बावड़ी जैसे चंद बची हुई धरोहरें भी आज पानी सहेजने के बजाय सिर्फ पर्यटन का केंद्र बनकर रह गई हैं। जबकि बाकी की सैकड़ों बावड़ियों को हमने कचराघर बना दिया या उन पर बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर दीं। जब पूरे शहर की जमीन पर कंक्रीट और डामर की अपेक्ष परत बिछ जाएगी, तो मानसून का पानी धरती के भीतर जाएगा कैसे?

द्रव्यवती नदी को संभारने के नाम पर उसे कंक्रीट के नाले में बदल दिया गया, और रामगढ़ बांध से लेकर आमेर की झीलों के भराव क्षेत्र पर भू-माफियाओं ने नेताओं और नौकरशाहों

की साठगांठ से कब्जा कर लिया। यही वजह है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण को राज्य के लचर और ढीले भू-जल नियमों पर सख्त धरौड़ा चलाना पड़ा और उनके दिशा-निर्देशों को खारिज करना पड़ा। आज स्थिति यह है कि मानसून की थोड़ी सी बारिश भी जयपुर की सड़कों को दरिया बना देती है क्योंकि पानी के पास जमीन के भीतर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हैरानी और क्षोभ की बात यह है कि इस पूरे जल संकट की बहस को चालाकी से केवल आम आदमी को व्यक्तिगत जिम्मेदारी बताकर छोड़ दिया जाता है। परकोटे के नागरिक से कहा जाता है कि वह नहाते समय बाटोटी का इस्तेमाल करे या ब्रश करते समय नल बंद रखे; जो कि नागरिक चेतना के स्तर पर बिल्कुल सही और जरूरी भी है।

लेकिन जयपुर के आसपास की उन विशाल व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों का क्या, जो हर दिन जो एक लीटर शौतल प्या, एक कपड़ा या एक टन कागज बनाने के लिए जमीन के सोने से लाखों लीटर पानी डकार जाती है? उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे इस जानलेवा जल-निशान पर नीति-निर्माता हमेशा रहस्यमयी चुप्पी साध लेते हैं। वार्षिक भू-जल गुणवत्ता रिपोर्ट के डरावने निष्कर्ष बताते हैं कि जयपुर के कई शहरी और औद्योगिक इलाकों का भू-जल अब सिर्फ खत्म हो रहा है, बल्कि वह फ्लोराइड और नाइट्रेट के अत्यधिक रिसाव के कारण जहरीला और पीने के लिए असुरक्षित हो चुका है। जयपुर का जल संरक्षण केवल पेड़ के नीचे बैठकर आसू बहाने या हर साल पांच जून को एक औपचारिक कार्यशाला आयोजित करने से नहीं

होगा। इसके लिए कड़े कानूनी और नीतिगत फैसलों की जरूरत है। नगर निगम के साथ ही राज्य सरकार को भी अब कड़े कदम उठाने होंगे ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। भवन निर्माण उप-नियमों के तहत जयपुर की हर नई और पुरानी व्यावसायिक और आवासीय इमारत में वर्षा जल संचयन को केवल कागजी नक्शों में नहीं, बल्कि जमीन पर अनिवार्य किया जाना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को अपने भारी-भरकम बजट का एक बड़ा हिस्सा जयपुर की परित्यक्त बावड़ियों और जोहड़ों की गाद निकालने और उन्हें पुनर्जीवित करने में लगाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी और महान सभ्यताएँ सोने या हथियारों की कमी से नहीं, बल्कि पानी की कमी के कारण नेस्तनाबूद हुईं। यदि हम आज भी इस भीषण हकीकत को देखकर कागजी आंखें मूंद रहे हैं, तो यकीन मानिए, अगला विश्व युद्ध सीमाओं के लिए नहीं, बल्कि पानी की आखिरी बोतल के लिए लड़ा जाएगा।

कंक्रीट के आलीशान मकान, चमचमती गाड़ियाँ और तिजोरियों में बंद पैसा आपको प्यास नहीं बुझा पाएँगे। प्रकृति हमें अपनी गलतियों सुधारने का आखिरी और अंतिम मौका दे रही है। यदि इस पर्यावरण दिवस पर भी हमारी नीति और नियत नहीं बदली, तो जयपुर का वैभव सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्नों पर बचेगा और आने वाली पीढ़ी हमारी इस आराधनात्मक लापरवाही के लिए हमें कभी माफ नहीं करेगी।

-मणिमाला शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक

“काँकरोच जनता पार्टी”.....डरना जरूरी नहीं है



राम निवास बैरवा

भारतीय उप महाद्वीप में कई देश हो सकते हैं, परन्तु सभी की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएँ लगभग एक जैसी ही हैं। इस उप-महाद्वीप के आंदोलन भी लगभग एक समान हैं। श्रीलंका में और बाद में बांग्लादेश में युवाओं का कथित आंदोलन जहाँ पुरानी राजनीतिक पार्टियों के हाथों चला गया, वहीं नेपाल में एक नई पार्टी बनाकर सत्ता प्राप्त की, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याओं के सुधारवादी उपायों के अलावा नेपाल में और कोई खास परिवर्तन नहीं किए जा सके।

भारत में भी उन्हीं समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी बनी, और दिल्ली में सरकार बनाकर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आँख की किरकिरी बनी। परिणाम किसी से छुपा नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों को जेल भेजा गया, बिना किसी प्रमाणित अपराध के। इसी से सीख लेकर तमिलनाडु में परम्परागत द्रमुक और अन्नादमक की रसाकतसी के बीच भाजपा ने फिल्म अभिनेता विजय थलपति (सी. जोसेफ विजय) को आगे करके उसकी टोवीके (Tamilaga Vettri Kazhagam TVK) नाम की पार्टी के जरिए तमिलनाडु की मजबूत पार्टियों को समाप्त करने की कोशिश की और सफल रही।

इसी बीच एक मामूली सी बात को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने व्यक्तिगत रूप से उलाहना देने वाले शब्द ‘काँकरोच’

का इस्तेमाल करके पूरे बेरोजगार युवाओं को ‘काँकरोच’ और ‘परजीवी’ कहकर उसे एक सामूहिक गाली में बदल दिया। “आम आदमी पार्टी” के एक पुराने कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई उस गाली को एक व्यंग के रूप में “काँकरोच जनता पार्टी” के नाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। देखते ही देखते करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर समर्थन करके उसे एक राजनीतिक पार्टी में बदल दिया। दीपके अरविंद केजरीवाल की तरह आम सभाएँ नहीं कर सकते थे, लेकिन शीघ्रता से प्रचारित-प्रसारित होने वाले सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों के बीच पहुँच बना ली। जैसा कि हमेशा ही होता है, सत्कार उस व्यक्ति या उन लोगों को व्यक्तिगत निशाना बनाना शुरू कर दिया है- जैसे कि युवा-बेरोजगार इस देश के दुश्मन हों और पाकिस्तान में बुरकर भारत सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक अभियान चला रहे हों।

“युवा कौन होते हैं और उनका भविष्य क्या है?” दरअसल युवक आवादी का वह हिस्सा होते हैं जिनको देश के भावी कर्णधार बताकर उनकी झूठी तारीफ की जाती है। पर वे सत्ताधारी लोगों और उनकी पार्टियों की नजरों में वही होते हैं जैसा सत्ता के एक प्रमुख अंग, मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें संबोधित किया है, ‘काँकरोच’, ‘परजीवी’।

वे परजीवी, काँकरोच क्यों हैं? कृषि अनगिनत बेरोजगारों को अपने में समाहित कर लेती है उन्हें भूखा नहीं मरने देती है। परन्तु आधुनिक और मॉडर्न शिक्षा पद्धति बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। वे युवा हैं, बेरोजगार हैं, परन्तु वे किसान नहीं हैं, वे मजदूर नहीं हैं, उनकी राष्ट्रीय उत्पादन में कोई भागीदारी नहीं है, उनकी राष्ट्रीय उत्पादन में कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए वे परजीवी हैं, इसलिए वे काँकरोच हैं। जब वे स्कूल, कॉलेजों नामक फैक्ट्रियों से बाहर निकलते हैं तो वे न तो युवा होते हैं न ही देश के कर्णधार। वे सिर्फ बेरोजगार होते हैं

जिन्हें रोजगार की तलाश है। और रोजगार देने वालों के लिए वे हिन्दू होते हैं, रोजगार देने वालों के लिए वे मुसलमान होते हैं, रोजगार देने वालों के लिए वे ईसाई और आदिवासी होते हैं। इससे भी आगे बढ़कर वे अनुसूचित जाति के होते हैं, वे अनुसूचित जनजाति के होते हैं, रोजगार देने वालों के लिए वे बनिया, गुप्ता, माहेश्वरी होते हैं। कहीं वे यादव होते हैं तो कहीं चमार होते हैं। लेकिन रोजगार देने वालों के लिए वे ‘कर्मचारी’ नहीं होते हैं, रोजगार देने वालों के लिए वे मजदूर नहीं होते हैं। वे सिर्फ नाकरी मांफे वाले होते हैं। इसीलिए वे एक वेकेंसी के पीछे सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे दौड़ते हैं.... ऐसे दौड़ते हैं... जैसे काँकरोच।

जब युवाओं की, देश के भावी कर्णधारों की कोई पहचान ही नहीं है तो वे सामन्तवाद के ताने-बाने से ही अपनी पहचान बनाते हैं। यही पहचान उन्हें काँकरोच बनाती है, यही पहचान उन्हें परजीवी बनाती है, जिन्हें परजीवियों की सत्ता अपने मनमुत्तलक दालकर उनका इस्तेमाल करती है। सरकार की नजरों में वे बेवकूफ बेरोजगार हो परन्तु वे दया के पात्र होते हैं, परजीवी हैं। शुक्र है न्यायाधीश महोदय ने उनको काँकरोच, परजीवी ही तो पहचान दी; ब्याख्या कॉलेजियम के अनुसार तो वे अदालत के अदब तक नहीं जाते।

आखिर वे अदाब कहाँ से सीखेंगे, जब रोजगार देने के नाम पर ली जाने वाली परीक्षाएँ एक मजाक बन कर रह जाती हैं। वैसे तो हर साल, कई वर्षों से परीक्षाओं के पेपर समय से पहले ही लीक कर दिये जाते हैं और नौकरियों के लिए चयन प्रक्रियाएं अंधर में लटकती की जाती हैं। इसी वर्ष, 2026 में नीट-यूजी की परीक्षाओं के पेपर लीक करवा के लाखों डॉक्टर- इंजिनियर बने का सपना देखने वाले बेरोजगारों को काँकरोच- परजीवी बनाने का ही तो तरीका है। ... और, ग्लोबलाइजेशन की कई शर्तों में से एक शर्त यही तो है कि प्रशासनिक खर्चों में 30 प्रतिशत की कमी करना होगा जिनमें नौकरियों को समाप्त करना भी शामिल है। नौकरियों कैसे खतम हों, खाली पदों का लालच दो पर उन्हें

पूरा नहीं करो। नौकरियों के इंतजार में युवा ओथरपुन होकर राजनीतिक दलों और माफियाओं के लिए काम करने वाले बनने को मजबूर होंगे ही।

सी.बी.एस.ई. के एक लडके वेदांत ने जब पूरी सरकार और सी.बी.एस.ई. के परीक्षा तंत्र और कामकर्मियों को उजागर किया तो पूरी सरकार, उसका मीडिया, पूरा सी.बी.एस.ई. तंत्र उस बच्चे को गलतसाबित करने की कोशिशें की और उनका ब्रह्मास्त्र भी चला कर उसे पाकिस्तानी कर दिया। युवाओं में सरकार को गलत साबित करने की पूरी क्षमता भी है, परन्तु सरकारी तंत्र के सामने बेबस हो रहे जाते हैं। जब वे सरकारी तंत्र को गलत साबित हैं तो वे महज युवा नहीं होते हैं, बल्कि वे देश की चिंता कर रहे होते हैं, वे एक इमानदार और जिम्मेदार सरकारी तंत्र की चाहत रखते हैं। उनकी इसी चाहत को खतम करने के लिए, उनकी इसी चाहत को जनता की, मजदूरों की, किसानों की अग्रिम वैचारिक पंक्ति नहीं बनने देने के लिए ही उन्हें काँकरोच और परजीवी की दिया जाता है।

ऐसे में राजनीतिक पार्टियाँ उन्हें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, आदिवासी, भंगी, चमार, यादव, जाट, ब्राह्मण, बनिया बनाकर उनका इस्तेमाल करती हैं। राजनीतिक पार्टियों के इस्तेमाल किए जाने के लिए पहली शर्त उन युवाओं का बेरोजगार होना जरूरी है। दूसरी शर्त, उनकी क्षमता पर निर्भर करता है कि वे संपत्तियों कितनी तोड़-फोड़ कर सकते हैं, कितना हंगामा कर सकते हैं, कितनी भीड़ इकट्ठा सकते हैं और कितना पैसा इकट्ठा करके पार्टी फंड के नाम से बड़े नेताओं को दे सकते हैं और अपनी खुद की आर्थिक स्थिति को भी अच्छी बनाकर अपनी ही जाति, अपने ही धर्म में सम्मानित व्यक्ति बनकर वाई मेंबर, सरपंच, एम.एल.ए, एम.पी. यहां तक कि मंत्री भी बन सकता है और अपने विवेक को अपनी बुद्धि को मेजें थपथपाने और हाथ खड़ा करने में प्रकट करता है।

लेकिन किसी युवा को न तो मजदूर बनने दिया जाता है और न ही किसानों वे अस्थायी मजदूर बन सकते

हैं। उनके जीवन में सामाजिक स्थायित्व नहीं आ पाता। इसी कारण वे किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन के संवाहक नहीं बन पा रहे हैं।

युवाओं आंदोलन कांति में नहीं बदलते हैं। मजदूरों के, किसानों के आंदोलन अंततः राजनीतिक कांति में बदल जाते हैं, जिनका पहला काम अर्थव्यवस्था को बदलना होता है। फ्रांस का 1793 का किसान आंदोलन “रोटी मांगने वाले किसान केक क्यों नहीं खाते” जैसे अबोध बच्ची के कथन को कटाक्ष मानकर फ्रांस के पूरे राजपरिवार को खतम कर चुका था। “काँकरोच-परजीवी” का कथन अबोध बच्ची जैसा कथन नहीं था, और ना ही मजदूरों-किसानों के लिए था बल्कि एक पीढ़ी, युवा पीढ़ी पर पूरे सरकारी तंत्र द्वारा किया गया कटाक्ष था।

संविधान के अन्तर्गत निर्मित सरकार और उसके विभिन्न अंगों का ढांचा दरअसल बच्चों और युवाओं का संरक्षक होता चाहिए लेकिन कोई भी सरकारी तामशास और संवैधानिक प्राधिकारी उन युवाओं का संरक्षक नहीं बन कर उन्हें तिरस्कृत करने में लगा है। पीढ़ियों के सामाजिक अन्तर को GEN-Z (जनरेशन-जेड) कहकर उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं जबकि भारत के युवाZEN-G (Zen-Generation) यानि कि शांत और गम्भीर पीढ़ी (जेन-जनरेशन) बनी हुई है और संवैधानिक व्यवस्था से अपनी अपेक्षाएं बनाए रखे हुए हैं। वे अभी आखरी पीढ़ी (Gen-Z) नहीं बनना चाहती, यह बात सरकारों और संवैधानिक पदाधिकारियों को समझ लेनी चाहिए।

नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने टिप्पणी की कि “क्षमता किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि संस्था में होती है। आपको इसी के लिए तैयारी करनी है।” फिर ‘काँकरोच’ और ‘परजीवी’ कहने वाले जस्टिस सूर्यकांत एक व्यक्ति थे या संस्था?

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्ता।

राशिफल

शुक्रवार 5 जून, 2026

द्वितीय ज्येष्ठ मास (अधिक), कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2083, श्रवण नक्षत्र शनिवार प्रातः 6:03 तक, ब्रह्म योग प्रातः 9:42 तक, कौलव करण दिन 12:26 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मेघ, बुध-मिथुन, गुरु-कर्क, शुक-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वाथ सिद्धि योग और कुमार योग सूर्योदय से सम्पूर्ण दिन-रात है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:19 तक, लाभ अमृत 7:19 से 10:43 तक, शुभ 12:25 से 2:07 तक, चर 5:32 से सूर्यास्त तक। राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:14

मेघ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बने लगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

तुला
व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगे।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक संदेश प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बने लगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

वृश्चिक
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बने लगे। अटका हुआ धन प्रदान होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मिथुन
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियों दूर होने लगेगी। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवाहित मामलों से

सतीश पूनियां और अलका गुर्जर को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया भाजपा ने

यह फैसला राजस्थान की दो प्रभावशाली जातियों जाट और गुर्जर वर्ग को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने राजस्थान के दो उम्मीदवारों के नाम घोषित कर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। पार्टी ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां और भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। यह फैसला केवल राज्यसभा सीटों तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे प्रदेश की दो प्रभावशाली जातियों जाट और गुर्जर समाज को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। गुरुवार देर शाम डॉ. सतीश पूनिया एवं डॉ. अलका गुर्जर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर मिठाई खिलाकर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं का व्यापक संगठनात्मक अनुभव, जनसेवा के प्रति समर्पण और राष्ट्रिय हित के प्रति प्रतिबद्धता संसद में राजस्थान एवं देश की आकांक्षाओं को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करेगी। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल उपस्थित रहे।



राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद डॉ. सतीश पूनिया एवं डॉ. अलका गुर्जर ने गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की।

लंबे समय से संगठन के महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा बनाए रखा और उन्हें पहले बिहार तथा बाद में हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी। अब राज्यसभा भेजने का निर्णय सक्रिय रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभा रही है। उम्मीदवार घोषित होने के बाद अलका गुर्जर ने बताया कि वे पार्टी की वर्चुअल बैठक में शामिल थीं, तभी केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का फोन आया और उन्हें टिकट मिलने की जानकारी दी गई।

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे सतीश पूनिया

हैं तथा संगठन में कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते ये सीटें रिक्त हो रही हैं।

अलका गुर्जर भी भाजपा की जमीनी राजनीति से जुड़ा बड़ा चेहरा हैं। वे एक बार विधायक रह चुकी हैं और गुर्जर समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके पति डॉ. नाथू सिंह गुर्जर भी भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके

ज्ञात रहे कि सतीश पूनियां वर्तमान में हरियाणा प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि अलका गुर्जर लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभा रही हैं।

है, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसे करीब 35 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। राजनीतिक समीकरणों के अनुसार यदि भाजपा को आरएलडी, निर्दलीय, बसपा और बीटीपी के सभी संभावित वोट भी मिल जाएं, तब भी तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए लगभग 20 वोट कम पड़ेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने फिलहाल दो उम्मीदवार उतारकर सुरक्षित रणनीति अपनाई है। हालांकि तीसरी सीट को लेकर अंतिम समय तक राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। यदि भाजपा तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो यह चुनाव केवल संख्या बल का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रबंधन और रणनीतिक कौशल की परीक्षा बन सकता है।

फिलहाल सतीश पूनिया और अलका गुर्जर की उम्मीदवारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा आगामी चुनावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

पीएम सूर्यधर योजना में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार

केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने डिस्कोम्स चेयरमैन को चार अलग-अलग श्रेणियों में प्रदान किए अवार्ड



केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित समारोह में ऊर्जा सचिव एवं राजस्थान डिस्कोम्स की चेयरमैन आरती डोगरा को चार अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए।

जयपुर (कास)। प्रधानमंत्री सूर्यधर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को सम्मानित किया है। केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किए। ऊर्जा सचिव एवं राजस्थान डिस्कोम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने चार अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार ग्रहण किए।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने योजना के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। इस दौरान

90 लाख से 1.50 करोड़ विद्युत उपभोक्ता वाले राज्यों के अंतर्गत में माह के दौरान रूप टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण तथा वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन का कैटेगरी में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इसी तरह सर्वाधिक इंस्टॉलेशन वाले 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की कैटेगरी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। जयपुर डिस्कोम्स की अधीक्षण अभियंता (पीएम सूर्यधर) महिमा साराभाई ने यह सम्मान ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त वेंडर श्रेणी में

मई माह के दौरान उत्तर क्षेत्र के राज्यों में सर्वाधिक रूप टॉप सोलर इंस्टॉलेशन की कैटेगरी में मिलन सौर ऊर्जा केंद्र को भी द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार राजस्थान को इस योजना में कुल 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष मई माह के दौरान इस योजना के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विवरण निगमों में 39279 आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 27700 आवेदकों का भौतिक सत्यापन किया गया, 26632 रूप टॉप सोलर इंस्टॉल हुए और 177 नए वेंडरों को योजना से जोड़ा गया।

बिना सूचना बाल कल्याण समिति में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर मांगा जवाब

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर की जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य पद पर बिना आम सूचना निकाले नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने पर बाल अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव, कमिश्नर व सदस्य सचिव सहित सहायक निदेशक से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने इन पदों की चयन प्रक्रिया को याचिका के निर्णयाधीन रखा है। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपिठ ने यह आदेश उदय भान सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

सिंह कुरकाने अदालत को बताया की याचिकाकर्ता भरतपुर जिले की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य पद पर आवेदन करना चाहते थे।

विभाग की ओर से अन्य जिलों में नियुक्तियों के लिए आम सूचना जारी की गई, लेकिन भरतपुर जिले की समिति के लिए कोई आम सूचना या भर्ती नोटिस जारी नहीं किया गया। याचिकाकर्ता को हाल ही में जानकारी मिली की जिला समिति के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।

ऐसे में याचिकाकर्ता ने बाल संरक्षण यूनिट के समक्ष आवेदन किया तो उसका आवेदन यह कहते

हुए लेने से इनकार कर दिया कि आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च को निकल चुकी है। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि भर्ती के लिए आम सूचना जारी करना जरूरी है, ताकि आमजन को इसकी सूचना मिले और इच्छुक व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकें। याचिका में गुहार की गई की आवेदन लेने की अंतिम तिथि बहाई जाए और उसकी आम सूचना जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार किए जाएं जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपिठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।

तीन दिन में 77806 किसानों से सीधा संवाद

जयपुर । कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने गुरुवार को पंत कृषि भवन में खेत बचाओ अभियान (1 से 30 जून) और खरीफ-2026 उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि अभियान के प्रथम तीन दिनों में प्रदेशभर में 2382 कृषि गतिविधियां आयोजित कर 77806 किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया है। इनमें 294 कृषक गोष्ठियों में 13273 किसान लाभान्वित हुए।

कांग्रेस ने नीरज डांगी को पुनः बनाया राज्यसभा उम्मीदवार

जयपुर। कांग्रेस ने राजस्थान से राज्यसभा सदस्य के लिए नीरज डांगी को मैदान में उतारा है। बता दें नीरज डांगी वर्तमान में कांग्रेस की ओर से राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल जून 2026 में खत्म होने वाला है। अब एक बार फिर उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया है। नीरज डांगी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, वह वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव पद पर भी कार्यरत हैं। डांगी सिलेज 30 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पार्टी में विभिन्न पदों पर भूमिका निभाई है। वे साल 2020 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। नीरज डांगी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत यूथ कांग्रेस से की थी। लगातार सक्रियता के चलते साल 2002 में वे राजस्थान यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष (वाइस प्रेसिडेंट) बने। नीरज डांगी को कांग्रेस ने उन्हें साल 2003 के विधानसभा चुनाव में देसूरी सीट से टिकट दिया, लेकिन वे चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2008 में पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए रेवदर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा, मगर वे 13वीं विधानसभा में भी नहीं पहुंच सके। चुनावी हार के बावजूद पार्टी ने उनकी निष्ठा को देखते हुए 2009 में उन्हें यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद 2014 में वे राजस्थान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनाए गए।

जयपुर में 302 सिलेंडर और दो पिकअप जब्त

जयपुर । घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और रीफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 302 गैस सिलेंडर और दो पिकअप वाहन जब्त किए हैं। राज्य सरकार और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई



जयपुर । घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और रीफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 302 गैस सिलेंडर और दो पिकअप वाहन जब्त किए हैं। राज्य सरकार और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई

■ अवैध गैस कारोबार पर जिला प्रशासन का शिकंजा

जिला कलक्टर संदेश नायक के निर्देशन में की गई। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि कार्रवाई के लिए दो विशेष सतर्कता दलों का गठन किया गया था। सतर्कता दल 'ए' में प्रवर्तन अधिकारी मुनेश कुमार मीणा और पूजा शर्मा तथा सतर्कता दल 'बी' में प्रवर्तन अधिकारी विनोद कुमार और प्रवर्तन निरीक्षक सुनीता चौधरी को शामिल किया गया। सतर्कता दल 'ए' ने सांगानेर क्षेत्र के गोवर्धन नगर और हनुमान सिटी में दबिश देकर अवैध गैस भंडारण और क्रय-विक्रय का खुलासा किया। यहाँ से 247 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर तथा दो पिकअप वाहन जब्त किए गए। वहीं सतर्कता दल 'बी' ने 310 फीट रोड स्थित शिक्षा सागर कॉलोनी में कार्रवाई कर 55 गैस सिलेंडर जब्त किए। दोनों स्थानों पर

की गई कार्रवाई में कुल 302 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर तथा दो पिकअप वाहन (आरजे-14-जीआर-7835 और आरजे-14-जीएच-5920) जब्त किए गए। मामले में सिलप दो व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

इस वर्ष 20 अरब रु. खर्च करके स्कूलों के नए भवन और क्लास रूम बनेंगे, मरम्मत भी होगी

स्कूलों के सर्वे और री-सर्वे से मिले फीडबैक के आधार पर सुधार कार्य कर रही राज्य सरकार

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । प्रदेश की सरकारी स्कूलों में नए भवन और क्लास रूम बनाने तथा पुराने जर्जर स्कूलों की मरम्मत पर भजनलाल सरकार इस वित्तीय वर्ष में 20 अरब रुपए खर्च करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के तमाम सरकारी विद्यालयों के भवनों का सुरक्षा की दृष्टि से सर्वे और री-सर्वे करवाया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नए भवन निर्माण और मरम्मत कार्य की 5 साल की कार्ययोजना बनाई है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 20 अरब रुपये के बजट से नए भवन निर्माण, अतिरिक्त सुविधाओं के विकास व मरम्मत कार्य होंगे।



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेकर स्कूलों के मरम्मत कार्य और नए निर्माण की समीक्षा की।

पर खरी उतरी है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों में नामांकन बढ़ने या अतिरिक्त विषय शुरू होने के कारण अधिकार संरक्षण आयोग की गाइडलाइन, बीआईएस के मानक और विशेष योग्यजन अधिनियम, 2016 के विनियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जा रही है। करीब 1 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्य में ऑन साइट क्वालिटी कंट्रोल लैब, 30 लाख रुपये से अधिक के कार्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग और नेशनल एक्रीडिशन

बोर्ड द्वारा चिह्नित एजेंसी द्वारा स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित किया है। बिजली बचत और बच्चों के स्वास्थ्य विशेषकर आई साइट के लिए पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था की गई है। स्टूडन्ट डिजाइन को राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा परीक्षण करने के बाद की स्वीकृति दी जा रही है। भवन की सुरक्षा और उत्तरजीवित सुनिश्चित करने के लिए आरसीसी फ्रेम डाला जा रहा है। दीवार और छत को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है, जिससे सीपेज और सीलन न हो। उपयुक्त ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था के

बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि विद्यालयों भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट मिलने से अधिक महत्वपूर्ण है, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, सिविल सोसायटी, भामाशाह और इंडस्ट्री का विद्यालयों की ज्यादा से ज्यादा निगरानी और उनसे जुड़ाव। उन्होंने सांसद-विधायकों से भी आग्रह किया है कि अपने स्थानीय फंड से यह कार्य करवाएं, इससे निगरानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को अपने फंड और विभिन्न योजनाओं से ये कार्य सीधे या कंबजैस के माध्यम से करवाने के लिए बातचीत की गई है। मगरा, डांग जैसी क्षेत्रीय विकास योजनाओं के फंड से भी ये कार्य करवाने का प्रस्ताव है। साथ ही डीएमएफटी और सीएसआर से भी फंड जुटाने का लक्ष्य है।

बैठक में समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परिचालना अधिकारी डॉ. रश्मि शर्मा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट वीसी के माध्यम से बीकानेर से जुड़े।

6 जून को राजस्थान आएंगे अजेय कुमार

जयपुर । भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त राजस्थान संगठन महामंत्री अजेय कुमार 6 जून को पहली बार राजस्थान प्रवास पर आएंगे। उनके दौरे की लेकर प्रदेश भाजपा संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अजेय कुमार के आगमन को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में उन्हें राजस्थान भाजपा के संगठन महामंत्री का दायित्व सौंपा गया है। सूत्रों के अनुसार, अजेय कुमार जयपुर में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी बैठक लेंगे। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों, बूथ सशक्तिकरण अभियान तथा कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न जिलों में चल रहे संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ होने वाली इस बैठक में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी रणनीति पर भी मंथन होने की संभावना है। विशेष रूप से राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों और संभावित रणनीति पर चर्चा होने की जानकारी सामने आ रही है। अजेय कुमार के दौरे को प्रदेश भाजपा के लिए नई ऊर्जा और अवसर था। गंगा दशमी में भव्य गंगा आरती, कलश पूजन और महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर अतिथियों और आमजन

वंदे गंगा अभियान में जयपुर जिला प्रदेश में अब्वल

40 हजार कार्यक्रमों में 27 लाख लोगों ने भागीदारी कर रचा इतिहास

जयपुर (कास)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जयपुर जिले में गत 25 मई से आयोजित हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जिला कलक्टर संदेश नायक ने गुरुवार को मीडिया संगोष्ठी में बताया कि गंगा दशमी के पावन पर्व से शुरू होकर 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) तक चलने वाले इस 12 दिवसीय महाअभियान के तहत जयपुर जिले ने 27 प्रदेश में सर्वाधिक सक्रियता दिखाते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है।

अभियान के दौरान जिले की ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में कुल 40 हजार से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 27 लाख से अधिक नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर जल संरक्षण को एक जन-आंदोलन का रूप दिया है। अभियान की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसका जिला स्तरीय शुभारंभ 25 मई को पवित्र गलता तीर्थ पर हुआ था। गंगा दशमी के शुभ अवसर पर गलताजी में भव्य गंगा आरती, कलश पूजन और महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर अतिथियों और आमजन

■ मानसून से पूर्व खोदे गए 20 लाख गड्डे, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में 26 करोड़ के नए कार्य स्वीकृत

■ उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आज मिलेगा जल गौरव सम्मान

ने गलता तीर्थ के प्राचीन जल कुंड के जीर्णोद्धार और सफाई के लिए ऐतिहासिक श्रमदान किया। इसी तर्ज पर जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन कर इस अभियान को गति दी गई।

मानसून से पूर्व 20 लाख गड्डे खोदे गए हैं, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में 26 करोड़ के नए कार्य स्वीकृत हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 5 जून को जल गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा।

अलवर में दिल्ली निवासी पादरी पर 15 लोगों को धर्मांतरण कराने का आरोप

मौके पर पहुंची पुलिस ने पादरी को हिरासत में लिया, 15 लोग मौके से फरार हो गए

अलवर, (निसं)। अलवर में धर्मांतरण के आरोप पर लोगों ने पादरी से मारपीट कर दी। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ता सूचना मिलने पर एक घर में घुसे, जहां ईसा मसीह की प्रार्थना चल रही थी। कार्यकर्ताओं ने पादरी को घर से बाहर निकाला, जबकि 15 लोग मौके से फरार हो गए। मौड़ ने पादरी के कपड़े भी फाड़ दिए। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो महिला पादरी को लात मारती हुई दिख रही है।



अलवर में धर्मांतरण के आरोप में विहिप कार्यकर्ताओं ने घर से बाहर निकाल पादरी से मारपीट कर दी।

चला। मौके पर पहुंची पुलिस ने पादरी को हिरासत में लिया। कार्यकर्ता आरोपी को पैदल ले जाने की मांग पर अड़ गए और पुलिस की गाड़ी के आगे खड़े हो गए।

विहिप के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि संगठन को

सूचना मिली थी कि तंवर कॉलोनी में धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना पर कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। घर में कुछ लोग एकत्रित होकर ईसा मसीह से जुड़ी प्रार्थना और धार्मिक पाठ में शामिल थे। विहिप कार्यकर्ताओं के पहुंचने के

■ मोबाइल की जांच में धार्मिक गतिविधियों से जुड़े वीडियो और अन्य सामग्री भी मिली

बाद करीब 15 जने मौके से फरार गए। कार्यकर्ताओं ने जब पादरी की तलाशी ली, तो उसके पास से धार्मिक साहित्य और प्रार्थना से जुड़ी किताबें मिलीं। मोबाइल की जांच में भी धार्मिक गतिविधियों से जुड़े वीडियो मिले हैं। नितिन ने बताया कि मैं दूसरी बार इस कार्यक्रम में शामिल होने आया था। घर में ईसा मसीह का पाठ कराया जा रहा था। लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही थी। सभा में दावा किया जा रहा था कि इस प्रार्थना को करने से सभी बीमारियां दूर हो सकती हैं। साथ ही, हिंदू देवी-देवताओं से दूर रहने की बातें भी कही जा रही थीं।

पूछताछ में पादरी राजकुमार ने बताया कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पिछले चार-पांच सालों से अलवर आता-जाता रहा हूं। लोगों को ईसा

मसीह से संबंधित धार्मिक पाठ और प्रार्थना करवाता हूं। दिल्ली में मेरी कपड़ों की दुकान है। विहिप कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर पादरी ने कहा कि मैं अब तक यहां करीब 15 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुका हूं। हंगामे की सूचना मिलते ही अखेपुरा थाना पुलिस एसएचओ महेश के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। पुलिस जब पादरी को वाहन में बैठाकर थाने ले जाने लगी, तो कुछ समय के लिए विहिप कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आरोपी को पैदल ले जाया जाए। बाद में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच समझाझ के बाद विधित शान्त हुई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने पहुंची।

अखेपुरा थाना प्रभारी महेश ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच में जुटी हुई है।

कोटा में कोचिंग छात्र ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की

कोटा, (निसं)। जवाहर नगर थाना इलाके में कोटा में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे कोचिंग छात्र ने बुधवार देर रात को कमरे में फांसी का फन्दा लगाकर आत्महत्या कर ली।

जानकारी के अनुसार सालभर से जवाहर नगर इलाके के राजीव गांधी नगर में एक पीजी में रहे रूपायु निवासी कोचिंग छात्र ने कमरे में फांसी का फन्दा लगा लिया, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छात्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बुधवार रात्रि को मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवाया और मृतक के परिजनों को सूचित किया गया।

■ यूपी निवासी कोचिंग छात्र कोटा में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था

जवाहर नगर थानाधिकारी रामलक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि उत्तरप्रदेश के संत कबीर नगर निवासी आर्यन ओझा (17) कोटा में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, छात्र ने राजीव गांधी नगर स्थित पीजी पर अपने कमरे में फांसी का फन्दा लगा लिया, सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक के परिजनों के कोटा पहुंचने

के बाद गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया, फिलहाल आत्महत्या के पीछे कोई कारण सामने नहीं आया है।

पुलिस उप अधीक्षक योगेश शर्मा ने बताया कि छात्र फेरवी माह में ही कोटा आया था तथा जेईई की तैयारी कर रहा था। प्रारंभिक दौर पर सामने आया है कि छात्र ने अभी कोई एजाम नहीं दिया था। छात्र के परिजन कोटा पहुंचे, परिजनों के कोटा पहुंचने पर परिजनों के कहने पर बिना पोस्टमार्टम के ही छात्र का शव उनको सौंपा गया है। वह शव को लेकर चले गए हैं। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। मामले में हर एंगल पर जांच की जाएगी।

मंदिर में हुई चोरी का खुलासा

■ चोरी का माल सहित दो जने गिरफ्तार

बिसाऊ, (निसं)। बुधुर्ग पुलिस ने शिव मंदिर में हुई चोरी की वारदात का महज छह घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी किया गया संपूर्ण सामान भी बरामद कर लिया है।

बिसाऊ थाना प्रभारी शेरसिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार, कस्बा बिसाऊ स्थित राजपूत समाज के मुक्तिधाम में बने शिव मंदिर में 1 जून को रात अज्ञात चोर ने मंदिर का ताला

श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मंदिर समिति से जुड़े नेत्र सिंह ने पुलिस थाना बिसाऊ में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और आसपास के लोगों से पूछताछ तथा सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी जाकिर खान (42) निवासी वार्ड संख्या 13, बिसाऊ को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की वारदात कबूल कर ली।

हनुमानगढ़ में 15 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

परिवादी के पिता के नाम इंतकाल दर्ज करने के बदले 30 हजार की रिश्वत मांगी

हनुमानगढ़, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ इकाई ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए चाहवाली पटवारी मंडल, तहसील टिब्बी के राजस्व पटवारी श्रीराम को 15 हजार रुपय की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पटवारी पर परिवादी के पिता के नाम इंतकाल (नामंतीकरण) दर्ज करने की एवज में 30 हजार रुपय की रिश्वत मांगने का आरोप है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी हनुमानगढ़ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजस्व पटवारी श्रीराम, निवासी डबली खुर्द, टिब्बी, परिवादी के पिता के नाम इंतकाल दर्ज करने के बदले 30 हजार रुपय की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उसका सत्यापन किया, जिसमें आरोप प्रथमदृष्टया सही पाए गए।



एसीबी ने राजस्व पटवारी श्रीराम को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

इसके बाद एसीबी टीम ने ट्रेप कार्रवाई की योजना तैयार की। एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस नारायण टोगस के सुपरविजन में हनुमानगढ़ इकाई की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधा पालावत के नेतृत्व में टीम का गठन किया

गया। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी पटवारी को 15 हजार रुपय की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम ने मौके पर आवश्यक साक्ष्य भी एकत्रित किए।

महिला पटवारी ने पांच हजार की रिश्वत ली

जयपुर/अलवर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अलवर प्रथम टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए खैरथल-तिजारा जिले की सांथलका तहसील टपुकड़ा की एक महिला पटवारी को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपित महिला परिवादी के पिता के निधन के बाद इंतकाल खोलने और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने की एवज में रिश्वत मांग रही थी।



एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके पिता के निधन के बाद स्वयं एवं अन्य

परिजनों के नाम इंतकाल दर्ज कराने तथा राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम सही

करवाने के लिए महिला पटवारी आशा देवी तीस हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही है। शिकायत के सत्यापन के दौरान 25 मई को एसीबी ने पाया कि आरोपित महिला पटवारी रिश्वत की मांग कर चुकी थी तथा परिवादी से पहले ही 10 हजार रुपये ले चुकी थी। इसके अलावा वह 5 हजार रुपये और देने का दबाव बना रही थी। इसके बाद एसीबी चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी शम्भू खान के नेतृत्व में ट्रेप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान महिला पटवारी आशा देवी को परिवादी से 5 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नितिन पुत्र बाबूलाल निवासी भूडनपुरा विषाक्त दवा के सेवन के बाद बेहोशी की हालत में मिला। उसे तत्काल उपचार के लिए सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार शुरू किया। अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों ने युवक को बचाने के हरसंभव प्रयास किए, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में लोगों की

विषाक्त दवा के सेवन से युवक की मौत

सूरजगढ़, (निसं)। क्षेत्र के भूडनपुरा गांव निवासी एक युवक की विषाक्त दवा के सेवन के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक को गंभीर अवस्था में आदर्श राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरजगढ़ में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नितिन पुत्र बाबूलाल निवासी भूडनपुरा विषाक्त दवा के सेवन के बाद बेहोशी की हालत में मिला। उसे तत्काल उपचार के लिए सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार शुरू किया। अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों ने युवक को बचाने के हरसंभव प्रयास किए, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में लोगों की

धीड़ जुट गई। घटना की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही परिजनों को घटना की सूचना देकर उनके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला विषाक्त दवा के सेवन का प्रतीत हो रहा है, लेकिन युवक ने यह कदमकित परिस्थितियों में उठाया, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। घटना के बाद भूडनपुरा सहित आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है तथा परिजन गहरे सदमे में हैं।

पावटा की साबी नदी के किनारे भारी मात्रा में “राजस्थान सरकार” लिखी दवाइयां मिलीं

पावटा, (निसं)। ग्राम राजनौता क्षेत्र की साबी नदी के किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। नदी क्षेत्र में खुले में पड़ी दवाओं की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां दवा की शीशियां बिखरी हुई दिखाई दीं। दवाओं की पैकिंग पर “राजस्थान सरकार” अंकित होने के कारण मामला गंभीर हो गया है और सरकारी दवा वितरण व निस्तारण व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।



पावटा के ग्राम राजनौता क्षेत्र की साबी नदी के किनारे सरकारी दवाइयां मिलने से हड़कंप मच गया।

पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

(बीसीएमएचओ) कृष्ण सिंह ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई है। प्रारंभिक स्तर पर संबंधित चिकित्सक द्वारा इन दवाइयों को अस्पताल के स्टॉक से जुड़ा होने से

इनकार किया गया है, लेकिन मामले की गहन जांच कराई जाएगी। दवाओं के बच नंबर, सफाई रिकॉर्ड और स्टॉक रजिस्टर की जांच के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि

■ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कृष्ण सिंह ने मामले को लेकर जांच करवाने के आदेश दिये

दवाइयां किस स्थान से आईं और नदी क्षेत्र तक कैसे पहुंचीं। बीसीएमएचओ ने कहा कि जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इधर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी दवाओं के रखरखाव, वितरण और निस्तारण की व्यवस्था की भी समीक्षा होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साबी नदी किनारे मिली सरकारी दवाओं की यह खेप अब केवल लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य संसाधनों की निगरानी और जवाबदेही से जुड़ा बड़ा सवाल बन गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।

अजमेर के पीसांगन क्षेत्र में कथित ‘लव जिहाद’ मामले में ग्रामीणों का प्रदर्शन

नाबालिग बालिका को वापस परिजनों को सौंपने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग

■ ग्रामीणों ने अजमेर कलैक्ट्रेट के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा

■ ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव की एक नाबालिग बालिका को आदिल नामक युवक ने प्रेम संबंधों के जाल में फंसाकर उससे निकाह कर लिया

अजमेर, (कासं)। पीसांगन तहसील क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका से जुड़े कथित ‘लव जिहाद’ प्रकरण को लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अजमेर जिला कलैक्ट्रेट के बाहर एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई।

नेत्र कुमार सेन समेत ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव की एक नाबालिग बालिका को आदिल नामक युवक ने प्रेम संबंधों के जाल में फंसाकर उससे निकाह कर लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बालिका अभी नाबालिग है, इसलिए पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए और उसे सुरक्षित रूप से उसके परिजनों को सौंपा जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि बालिका के परिवार को न्याय दिलाने के लिए वे लंबे समय से प्रशासनिक स्तर पर गृहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले में शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जाए

तथा यदि कोई संगठित गिरोह सक्रिय है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की ब्यापक चोरी के पीछे यदि कोई नेटवर्क या गिरोह कार्य कर रहा है तो उसकी भी गहन जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी पता लगाया जाए कि ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता या फंडिंग कहाँ से प्राप्त हो रही है।

प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नाबालिग बालिका की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा पंडित परिवार को न्याय दिलाने की मांग

की गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी तथ्यों की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई और परिणाम को न्याय नहीं मिला, तो क्षेत्रभर के लोगों को साथ लेकर एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण समाज में भारी आक्रोश है और लोग प्रशासन से त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों का बात सुनी और मामले को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर जांच करवाने का आश्वासन दिया।

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक ब्लीकट डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट, अपहरण, तोड़फोड़ और लूटपाट का मामला सामने आया है। सिर्फ गाड़ी टच होने के मामले में विवाद को लेकर कुछ युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के विरोध में आक्रोशित होकर बड़ी संख्या में ब्लीकट के डिलीवरी पार्टनर्स गांधीनगर थाने के बाहर एकत्रित हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन कर रहे साथी कर्मचारी बबलू सिंह ने बताया कि ब्लीकट कंपनी का डिलीवरी बॉय गजेंद्र सिंह गुरुवार सुबह पुलिस लाइन इलाके में एक ऑर्डर की डिलीवरी देने गया था। इसी दौरान उसकी बाइक एक अन्य वाहन से टच हो गई। गजेंद्र सिंह ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और वाहन को हूए नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही, लेकिन इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति शांत नहीं हुआ और विवाद बढ़ता चला गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद पुलिस ने गिरोह से जुड़े किशनलाल तथा अशोक पुत्र महेश कुमार जाट को पकड़ लिया।

फिर फोन करके अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया। इसके बाद आरोपी युवक गजेंद्र सिंह को जबरन अपने साथ उठाकर एक घर में ले गए। वहां बंधक बनाकर उसके साथमारपीट की गई, जिससे गजेंद्र सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों ने गजेंद्र सिंह का मोबाइल फोन तोड़ दिया और उसकी बाइक को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोपियों ने उसके पास रखे चार हजार घण्ट भी जबरन छीन लिए। जब डिलीवरी बॉय के साथियों को इस घटना का पता चला और उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस में करने की बात कही, तो दबंग आरोपियों ने उन्हें खुलेआम धमकी दी। आरोपियों ने कहा कि “उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता”। जिसके बाद सभी एकजुट होकर गांधीनगर थाने पहुंचे और तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर घरने पर बैठ गए। उन्होंने दोटुक शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक प्रदर्शन और कामबंद हड़ताल लगातार जारी रहेगी।

पिछली सरकार की 30 हजार किमी की तुलना में हमने 48 हजार किमी सड़कें बनाईं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए

जयपुर, 4 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़कों का निर्माण परदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण को निरंतर जांच की जाए एवं निम्नस्तरीय सड़क पर अधिकारी-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जालौर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, कोटपूतली, अजमेर, बाँसवाड़ा के बीच कनेक्टिविटी को यथा शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

अभियंता की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को, उच्च गुणवत्ता के मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए आपसी



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा व अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता मौजूद थे।

समन्वय से तय समयसीमा में पूरा किया जाए। विकास एवं परियोजनाओं के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित हो।

उन्होंने प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जालौर-झालावाड़, श्रीगंगानगर-कोटपूतली, अजमेर-बाँसवाड़ा के मध्य बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रगतिरत कार्यों के बारे में अवगत

करवाते हुए बताया कि वर्तमान सरकार के 2 वर्ष 5 माह के कार्यकाल में अब तक 33 हजार 195 करोड़ रुपये का व्यय कर 48 हजार 748 किमी लम्बाई में सड़कों का विकास कार्य पूर्ण किया गया है। जिसमें से 17 हजार 934 किमी लम्बाई की नवीन सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार में समान समयवधि के दौरान 13 हजार 400 करोड़ रुपये व्यय कर 30 हजार 641 किमी लम्बाई में सड़कों का

निर्माण कार्य ही किया गया था। वहीं, नवीन सड़कें भी केवल 4 हजार 671 किमी लम्बाई में निर्मित की गई थीं। साथ ही, केवल 280 गांव ही सड़कों से जुड़ पाए थे।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा व अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता सहित, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

‘ईरान वॉर से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ट्रंप प्रशासन का जोर देकर कहना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका है, जबकि, दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच लगातार गोलीबारी जारी है और शांति वार्ता में वास्तविक प्रगति के संकेत नहीं दिख रहे हैं। डेमोक्रेट्स ट्रंप पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने फरवरी के अंत में कांग्रेस की अनुमति के बिना इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए थे। “युद्ध शक्तियाँ अधिनियम (वॉर पावर्स एक्ट) के तहत, अमेरिकी सेना को किसी भी संघर्ष में उतराने के बाद राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की मंजूरी लेने के लिए 60 दिन का समय होता है। वह समय सीमा कई सप्ताह पहले ही बीत चुकी है, और डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप अब कानून तोड़ रहे हैं। वाइट हाउस इस व्याख्या को

स्वीकार नहीं करता और उसका तर्क है कि अप्रैल में हुए संघर्ष-विराम के कारण यह समय सीमा अस्थायी रूप से रूक गई थी। लेकिन ट्रंप ने बार-बार हमले फिर से शुरू करने की धमकी दी है, और इस सप्ताह तनाव और भी बढ़ गया है। रता-रत, अमेरिका ने बताया कि उसने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है और ईरान के एक जमीनी नियंत्रण केन्द्र पर हमला किया है, वहीं दूसरी ओर, तेहरान की सेनाओं ने खाड़ी क्षेत्र के कई पड़ोसी देशों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। ट्रंप का समर्थन करने वाले रिपब्लिकन नेताओं ने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव ऐसे समय में अमेरिका को कमजोर करेगा, जब ईरान दबाव में है। लेकिन नवंबर में होने वाले मध्यवर्धि चुनावों से पहले युद्ध का राजनीतिक बोझ बढ़ने के कारण, उनकी नाराजगी भी अब अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी है।

सीजेपी को रैली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कर ली है और लाखों समर्थक जुटा लिए हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसकी तुलना हाल के वर्षों में दुनिया भर में उभरे उन ऑनलाइन आंदोलनों से कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति पर प्रभाव डाला था। इस सन्दर्भ में, 2010-12 के “अरब स्प्रिंग आंदोलन” और 2011 के “ऑक्सियाई वॉल स्ट्रीट” आंदोलन का भी उल्लेख किया जा रहा है। पिछले एक दशक में हॉंगकांग, ब्राज़ील और फिलीपींस से कई हैशटैग आंदोलनों की खबरें आई हैं। इसी तरह के युवा आंदोलनों ने, भारत के पड़ोसी देशों, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी बड़े राजनीतिक बदलावों को जन्म दिया है। अब यह देखना बाकी है कि दिपके और उनके सहयोगी अपने ऑनलाइन अभियान को जमीन पर वास्तविक जन आंदोलन में बदल पाते हैं या नहीं। सीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है, वे

काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इनमें धर्म-प्रधान का इस्तीफा, शासन में अधिक जवाबदेही, भ्रष्टाचार विरोधी कदम, गोदी मीडिया की जांच और राजनीतिक दल-बदल की जांच जैसी मांगें शामिल हैं। सीजेपी राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी वकालत करती है। इसके अलावा, पार्टी संस्थागत ईमानदारी को मजबूत करने और मतदाताओं को प्रभावित किए जाने की धारणाओं को कम करने की बात भी करती है।

चने की डोल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रतिभाशाली दीक्षा कुशवाह उच्छ्रित विद्यालय की कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हैं। वह शहर के शहर के फ्रीगंज स्थित एक आर्ट क्लास की भी छात्रा हैं।

खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले में नया मोड़

खान सर व कोचिंग सेंटर के गार्ड्स से पूछताछ की गई

पटना, 04 जून। खान सर के कोचिंग में हमले के मामले में अब उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं इसी बीच खान सर की कोचिंग जीएस ग्लोबल स्टडीज में हुए पधवार वाले दिन जो गार्ड ड्यूटी पर थे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की थी, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर फायरिंग का आरोप है। दोनों

गार्ड्स के हथियारों की प्रामाणिकता भी जांची जा रही है।

गार्ड्स के हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं और उनके लाइसेंस का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। खान सर के जिन दो बाँडिंगार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम प्रदीप और तालेश्वर हैं। खान सर से पुलिस ने उनकी

कोचिंग जीएस ग्लोबल स्टडीज में ही पूछताछ की है, ये पूछताछ काफी देर तक चली है। बताया जा रहा है कि अभी खान सर से और भी पूछताछ हो सकती है। इस मामले में पुलिस उनसे हर जानकारी ले रही है। दरअसल खान सर

की कोचिंग में हुए हंगामे में तोड़ फोड़ और फायरिंग की खबर के बाद, खान सर ने खरिद फायरिंग की बात से मना किया था। एफआईआर में भी फायरिंग की बात दर्ज नहीं थी। लेकिन खान सर के इनकार करने के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में हवा में दो लोग फायरिंग कर दिख रहे थे।

टीएमसी के विधायकों ने जो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अधिकतर बजटों के प्रति अपने गहरे रोप, यहाँ तक कि घुणा, को खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी कहानियाँ भी सामने आ रही हैं कि चुनावी पराजय के बाद वरिष्ठतम विधायकों को भी इस विद्रोह तहस्ती के सम्मान में खड़े होकर तालियाँ बजाने के लिए मजबूर किया गया था। अगर ऐसा होता है, जैसा कि कई लोग मानते हैं कि यह भी समय की बात है, तो तृणमूल कांग्रेस के अधिकांश सांसदों का ऋतुरत बजटों गुट में जाना केवल उस व्यापक स्थिति का परिचायक होगा, जिससे पार्टी गुजर रही है।

तृणमूल कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधि, एक के बाद एक, पार्टी और अपने पदों को छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक नाम बिधानमन्तर नगर निगम की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती का है, जिन्होंने आज अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में पुष्टि की कि मौजूदा परिस्थितियों में काम करना अब संभव नहीं रहा है। हालाँकि उसी बिधानमन्तर क्षेत्र से निर्वाचित एक भाजपा विधायक ने दावा किया कि वे इसलिए पद छोड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कथित रूप से अत्यधिक बढ़ी हुई संपत्ति के उजागर

होने का डर है। बताया जाता है कि उनके पास 17-18 संपत्तियाँ हैं, जो वर्तमान में गैस्ट हाउस के रूप में संचालित हो रही हैं। इसके अलावा, उन्होंने अन्य अचल संपत्तियाँ भी अर्जित की हैं। पत्रकारों से बात करते समय वे दशकों की जनसेवा के बाद पद छोड़ने की बात करते हुए धातुक हो गई और उनकी आँखों में आँसू थे।

उदाहरण के लिए, एनआईए पूरे दिन तृणमूल के कुख्यात बाहुबली सौकत मोल्ला को पकड़ने की कोशिश करती रही। मोल्ला पर चुनाव से पहले कोलकाता के निकट भांगड़ क्षेत्र में हुए एक कथित बम हमले में शामिल होने का संदेह है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। सौकत मोल्ला की तलाश के दौरान, एनआईए की उनके विशाल संपत्ति समग्रण का भी पता चला, जिसमें मकान, कैफे, रेस्तराँ, इमारतें तथा कथित रूप से एक बारहमासी नदी

की भूमि पर अवैध कब्जा शामिल है। आरोप है कि सौकत ने नदी के पानी का प्रवाह रोककर, उसके किनारे विशाल क्षेत्र में भूमि विकसित कर ली थी, जिसका क्षेत्रफल हजारों एकड़ बताया जाता है। उनके बेटे ने उस भूमि पर एक कैफे बना लिया है और उनके भाई उसी क्षेत्र में एक पॉप सितारा होटल का निर्माण कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण कथित रूप से हत्या और धमकी के डर से विरोध नहीं कर सके।

कहा जाता है कि स्थानीय पुलिस भी सौकत मोल्ला और उनके पुत्र के प्रभाव में थी। एनआईए ने अब सौकत को 8 जून को तलब किया है, लेकिन माना जा रहा है कि वे उपस्थित नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में अब कथित भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, और दबंगों तथा पूर्व शासन - संरक्षित लोगों द्वारा किये गये अत्याचारों को लेकर व्यापक आक्रोश और विरोध दिखाई दे रहा है। ऐसे मामलों की संख्या इतनी अधिक बताई जा रही है कि किसी भी बेहद समर्पित व निष्पक्ष सरकार के लिए भी इनसे एक साथ निपटना मुश्किल है। जनता की अपेक्षाएं बहुत ऊँची हैं और यह एक पहेली बनी हुई है कि इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा।

केरल में मानसून ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कारण दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद तापमान में आई गिरावट से लोग राहत महसूस कर रहे हैं और शूलसा ने वाली गर्मी से छुटकारा मिलने पर संतोष जता रहे हैं। स्थिति को देखते हुए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 4 जून से 5 जून तक के लिए क्षेत्र में पुनः “थेलो अलर्ट” जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो दिनों तक दिल्ली-पनसीआर में आसमान मुख्यतः बादलों से ढका रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार, इस अवधि में हल्की से मध्यम बारिश, बार-बार गरज के साथ छोटे पड़ने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएँ चलने की संभावना है, विशेषकर दिन के उत्तरार्ध में। दक्षिण भारत में मानसून के समय से पहले पहुंचने के कारण, उत्तर भारत के वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ गई है, जिससे प्री-मानसून गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। जैसे-जैसे यह नम हवा उत्तर की ओर बढ़ रही है, वह दिल्ली-पनसीआर की स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के साथ मिलकर तेज हवाओं, धूलभरी आंधियों और अनियमित गरज-चमक वाले तूफानों

मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगी, पांच की मौत

मुजफ्फरपुर, 04 जून। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित प्रसाद अस्पताल में लगी भीषण आग की घटना में अब तक 05 लोगों की मौत हो चुकी है। नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने इसकी पुष्टि की है। आग तड़के करीब 3 बजे अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी थी। इसके बाद देखते ही देखते पूरे अस्पताल में घुआँ फैल गया। इससे अस्पताल परिसर के अंदर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर

अभी तक की जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है।

पहुँची दमकल टीम ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घटना में अब तक 05 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्मार्ट चौधरी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुःख है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग एमपी से राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित

भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, मणिपुर व राजस्थान से प्रत्याशियों की घोषणा की

अरुणाचल से ताई तागाक, गुजरात से राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, राजस्थान से डॉ. सतीश पूनिया और अलका गुर्जर, मणिपुर से शारदा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है।

नई दिल्ली, 04 जून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केन्द्रीय चुनाव समिति ने पांच राज्यों में होने वाले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव-2026 तथा ओडिशा में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दो सीटों से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ संगठनात्मक नेता रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा, बीजद छोड़ कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए देवाशीष सामंतराय को ओडिशा उपचुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है।

भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान की 10 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव और ओडिशा की एक

सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। इसमें अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक, गुजरात से राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जितेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया, मध्य प्रदेश से मणिपुर से ए शारदा देवी तथा राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पूनिया को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाए गए तरुण चुग भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन के प्रमुख रणनीतिकारों

में गिने जाते हैं। पंजाब के अमृतसर से आने वाले चुग जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना सहित कई राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं।

दूसरे उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल लंबे समय से मध्य प्रदेश भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं। वे वर्तमान में प्रदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

उल्लेखनीय है कि 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के बाद, उसी दिन मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे।

मालविया नगर अग्निकांड के मृतक के परिजनों को 10 लाख रु. की सहायता

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सभी मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

नई दिल्ली, 04 जून। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मालवीय नगर अग्निकांड में घायल लोगों का हाल चाल जानने के लिए साकेत स्थित अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की, उनके परिजनों से बात की और डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं, गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिन मृतकों के परिजन अन्य राज्यों या विदेशों में रहते हैं, उनके

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के होटलों, व्यावसायिक परिसरों व अन्य सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों की विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिये।

पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक उनके घर तक पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ तुरंत की जाएं। अस्पताल में भर्ती घायलों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें ढाँढ संभालते हुए कहा कि दिल्ली सरकार उनके साथ है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने चिकित्सकों से प्रत्येक मरीज की स्थिति की व्यक्तिगत जानकारी ली और उपचार प्रक्रिया को निरंतर निगरानी बनाए रखने

के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ मरीज गंभीर स्थिति में हैं और कुछ को वैटिलेटर पर रखा गया है। प्रभावितों में, भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, कैमरून, लीबिया सहित अन्य देशों के नागरिक भी हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और विदेशी नागरिकों के मामलों में भी आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया

जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी में सुरक्षा संबंधी कई गंभीर कमियाँ सामने आई हैं। कई भवनों में आपातकालीन निकास मार्ग, फायर सेफ्टी सिस्टम और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाती। उन्होंने संबंधित विभागों को घटना की विस्तृत जांच कराने और राजधानी के होटलों, व्यावसायिक परिसरों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां भी लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होगी, वहां जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

‘हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ेगा’

बेरूत, 04 जून। इजरायल और लेबनान के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम समझौते को लेकर नया विवाद खड़ा हो चुका है। लेबनान के शक्तिशाली संगठन हिज्बुल्लाह ने इस समझौते को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा है कि मौजूदा प्रस्ताव उसे स्वीकार्य नहीं है और इससे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकेगी।

हिज्बुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने स्पष्ट किया है कि जब तक दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी बनी रहेगी, तब तक उनका संगठन प्रतिरोध जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी युद्धविराम की शर्त यह होनी चाहिए कि इजरायल पूरी तरह लेबनानी क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुलाए और सैन्य कार्रवाई पूरी तरह समाप्त करे। कासिम ने लेबनानी सरकार और इजरायल के बीच चल रही बातचीत पर भी सवाल उठाए।

इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके

चेन्नई, 04 जून। द्रविड़ मुनेत्र कडगम (डीएमके) ने आठ जून को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग न लेने का फैसला किया है। पार्टी ने कांग्रेस पर तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। बता दें कि मीडिया प्रस्ताव उसे स्वीकार्य नहीं है और विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस, डीएमके का चुनाव छोड़कर टीवीके के साथ गठबंधन में शामिल हो गई थी, जिसे डीएमके ने धोखा करार दिया था। बता दें कि डीएमके इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगियों में से एक थी।

बनारस में डीएमके ने कहा कि वह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। पार्टी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन, नगरपालिका संशोधन अधिनियम (सीएए), चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, वन नेशन, वन इलेक्शन

आज पत्ने खोलेंगे अन्नामलाई

चेन्नई, 04 जून। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने शुक्रवार, पांच जून 2026 को दोपहर 12:00 बजे एक बड़े सोशल मीडिया संबन्ध का घोषणा की है। इस एक एलान ने राजनीतिक हलकों में अटकलें का बाजार बेहद गरम कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक अब उनके अगले कदम को लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अन्नामलाई भाजपा से दूर बनाने या पार्टी छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहां उन्होंने केन्द्रीय मंत्री भी अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन मोदी समेत शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे केन्द्रीय आलाकमान को अपना इस्तीफा भी सौंप चुके हैं।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पुलिस ने कहा कि वे एफआईआर को काँपी देंगे। तीन जून को दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 21 लोगों की धुएँ और आग की चपेट में आने से मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे।

ओटीएस चौराहे पर फ्लाईओवर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस प्रकरण में प्रथमदरजाया प्रभारी अधिकारी की ओर से अदालत में गलत बयानबाजी की गई है, जिसके तथ्य रिकॉर्ड से अलग पाए गए हैं। ऐसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सक्षम अधिकारी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से काम करना होगा। राजनीतिक कारणों से सरकार अपने संविदात्मक दायित्वों से बच नहीं सकती है। जेडीए एक तरफ कह रहा है कि कंपनी की वजह से देरी हुई, लेकिन दूसरी ओर जेडीए ने बिना चुपनी लगाए कंपनी को उसकी बैंक गारंटी लौटा दी। यह कृत्य अदालत को गुमराह करने वाला है।

याचिका में कहा गया कि जेडीए ने ओटीएस चौराहे को सिग्नल फ्री और सौंदर्यकरण कराने को लेकर टेंडर निकाले थे। याचिकाकर्ता जेसीएल इंफ्रा प्रा. लि. को टेंडर मिलने के बाद कंपनी को 6 जनवरी 2023 से 5 जनवरी 2024 तक काम पूरा करना था। इसी बीच सरकार बदलने के बाद जेडीए ने अनुबंध की शर्तों का हवाला देते हुए 24 अप्रैल 2024 को ठेका वापस ले लिया। इसके बाद 16 दिसंबर को याचिकाकर्ता की बैंक गारंटी भी वापस कर दी। वहीं

3 अप्रैल, 2025 को ओटीएस चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण की डी.पी.आर. बनाने के लिए 83 करोड़ रुपये का नया टेंडर जारी कर दिया। अधिवक्ता एस.एस.होरा ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी को दिया हुआ ठेका बिना किसी कारण और सुनवाई किए जेडीए ने वापस लिया है, जबकि कंपनी ने ड्राइंग्स और डिजाइन तैयार कर अनुमोदन के लिए पेश कर दिए थे। कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए थे, लेकिन जरूरी अनुमति या व साइट पर जमीन मुहैया नहीं करवाने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन कारणों की वजह से लिया गया है, जो याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट डी.पी.आर. द्वारा प्रोजेक्ट बदलने के 2023 में दिये गए ज्ञापनों पर जेडीए के अधिकारियों ने नया प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था। अधिवक्ता एस.एस. होरा ने कहा कि डॉ.पी.पी.आर. के लिए टेंडर निकालना पहले से तैयार डी.पी.आर. और प्रोजेक्ट को निरस्त करने जैसा है, जबकि कंपनी ने 64 बार पत्र लिखकर प्रोजेक्ट के ड्राइंग्स अप्रवृत्त के लिए लिखा था।

उपर जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि याचिकाकर्ता को कई

मौके देने के बाद भी काम शुरू नहीं होने पर नियमानुसार ठेका निरस्त किया गया है। इसके अलावा अब वहां 184 करोड़ रुपये के बजट 83 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर बनना है। जेडीए की तरफ से कहा गया कि जेसीएल इंफ्रा ने समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जरूरी डिमांड व ड्राइंग्स जेडीए को उपलब्ध नहीं कराए थे और अनुबंध के अनुसार, उपयुक्त अधिकारी (स्थानीय एक्सपर्ट) ने समयबद्धि पूरी होने के बाद उचित प्रक्रिया से अनुबंध निरस्त किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फ्लाईओवर बनाने के लिए जारी डीपीआर को रद्द कर पुराने अनुबंध के आधार पर प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है।

राज्यसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रदेश से पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया गया है। राजस्थान से नीरज डोंगी को देवारा राज्यसभा भेजना भी फंसला किया गया है, जबकि तमिलनाडु से अर्थशास्त्री और पार्टी के रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड से प्रणय झा को भी राजस्थान चुनाव के लिए मैदान में उतारा है।